सलवा जुडुम बंद करो!!

दंतेवाडा में हिंसा रोको!!

जून 2005 से छत्तीसगढ सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी जनता के "स्वत:स्फूर्त", "शांतिपूर्ण" "जन आंदोलन" सलवा जुडुम के नाम पर युद्ध छेडे हुए है । प्रशासन ने यह दावा किया कि नक्सलियों द्वारा विकास कार्य एवं तेंदूपत्ता तोडाई पर लगाई रोक से तंग आकर 200 गांवों के लोग जगह जगह मीटिंग और रैलियां कर रहे हैं ।

सलवा जुडुम का यह चित्रण सत्य से काफी परे है । सत्य यह है कि सलवा जुडुम का नेतृत्व स्थानीय धनी लोगों, ठेकेदार एवं व्यापारियों के हाथ में है और यह नक्सलवाद से सरकारी लडाई का आधिकारिक हिस्सा है और इसे छत्तीसगढ सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है । सलवा जुडुम के कार्यकर्ता बंदूक, लाठी, तीर धनुष और टंगिया से लैस होते हैं और यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है । जनवरी 2007 तक छत्तीसगढ पुलिस अधिनियम के अधीन 4048 विशेष पुलिस अधिकारी भर्ती किये गये हैं । इन्हें सरकार से शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये लोग सलवा जुडुम के साथ सक्रिय भागीदारी करते हैं । इस तरह ये लोग सरकार के नक्सल विरोधी कार्यक्रम में पुलिस के समानांतर काम करते हैं ।

यद्यपि इस बारे में बिल्कुल सही आंकडा मिलना मुश्किल है पर पिछले 2 सालों में 1,00,000 से अधिक लोग सलवा जुडुम के कारण अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, इसके साथ ही 644 गांवों के 3 लाख लोगों का जीवन आज पूरी तरह अस्त व्यस्त है जो कैम्पों पर नहीं आए हैं । इन लोगों को "नक्सली समर्थक" समझा जाता है और इन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम सहायताएं बंद कर दी गई हैं । इन लोगों को बाज़ार या सडकों पर भी नहीं आने दिया जाता । लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से हकालकर "रिलीफ कैम्पों' में लाया जा रहा है । इन कैम्पों की हालत अत्यंत दयनीय है जहां लोगों को खाद्यान्नों की कमी के साथ अस्वास्थ्यकर स्थिति में रहने को मजबूर होना पड रहा है । उन हज़ारों लोगों को जिन्हे पडोसी राज्यों में भागकर जाना पडा है उनकी स्थिति और भी दयनीय है ।

दंतेवाडा जिले पर प्रशासन की पकड पूरी तरह से जा चुकी है । सलवा जुडुम किसी को भी नक्सल समर्थक होने के शक पर डराने, धमकाने और सज़ा देने का काम करता है । सलवा जुडुम कार्यकर्ताओं द्वारा की गयी हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की कोई शिकायत दर्ज़ नहीं की जाती । सरकार सलवा जुडुम के कार्यकलापों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती वरन उन्हें संरक्षण देने के साथ साथ यह सब करने के लिये पूरी मदद देती है इस कारण जिले में सलवा जुडुम का दर्ज़ा कानून से परे की संस्था की तरह हो गया है ।

सरकार नक्सलियों से सिर्फ हिंसक लडाई ही लड रही है और इस योजना के तहत उसने सामान्य लोगों को नक्सलियों और एक दूसरे के खिलाफ लडा दिया है । इस तरह की कार्ययोजना से सरकार ने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के तरीके को छोड दिया है । आदिवासियों द्वारा नक्सलियों के समर्थन के मूल कारण भूख, गरीबी से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है । राज्य सरकार के अपने आंकडों के अनुसार भी सलवा जुडुम ने संघर्ष को और तेज़ किया है ।

हमारी मांगें

छत्तीसगढ सरकार से:

1. सलवा जुडुम को तुरत बंद किया जाए व उनके अस्त्र वापस लिए जाएं
2. स्पेशल पुलिस फोर्स की भर्ती पर रोक लगे
3. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और युवकों कि भर्ति बंन्द करो
4. आदिवासियों को उनके गांव वापस जाने दिया जाए; जहां पर भी घर और सम्प्न्नी नश्ट की गाईं है, सरकार उनको दोबरा बना कर दे
5. पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का दंतेवाडा में कहीं भी जाने की खुली छूट हो एवं उन पर अत्याचार बंद हो
6. छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा कानून 2005 रद्द किया जाए
7. बातचीत के लिये उपयुक्त माहौल तैयार करें एवं राजनैतिक समस्याओं का राजनैतिक हल तलाशा जाए
8. मानव अधिकार कार्यकर्तो ऒर सामजिक कार्यकर्तो को झूटे आरोपो पर गिरफ़तार करना ऒर उन्हे प्रताडित करना बंन्द करें; ऐसे सभी कार्यकर्तो को रिहा करें

भारत सरकार से :

1. स्थानीय विरोधी समूहों की मदद की नीति के नाम पर सलवा जुडुम का समर्थन एवं सहयोग बंद करें
2. सलवा जुडुम एवं पुलिस द्वारा की गई प्रत्येक हिंसा, बलात्कार, आगजनी, लूट, हत्या एवं गायब होने की घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो
3. छत्तीसगढ के बाहर रह रहे विस्थापित आदिवासियों की सुरक्षा एवं मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो
4. बातचीत के लिये उपयुक्त माहौल तैयार करें एवं राजनैतिक समस्याओं का राजनैतिक हल तलाशा जाए

सीपीआई (माओवादी) से :

1. प्रत्येक तरह की हिंसा बंद हो
2. अपने गांव लौटने वाले सलवा जुडुम समर्थक सहित संभी ग्रामीणों की रक्षा की ज़िम्मेदारी लें
3. बातचीत के लिये सही माहौल तैयार करें एवं राजनैतिक समस्याओं का राजनैतिक हल तलाशा जाए

सांसदों से अपील:

संसद में इस मुद्दे को उठाएं एवं गृह मंत्रालय की स्थानीय विरोधी समूहों की मदद की नीति और खासकर सलवा जुडुम की मदद की नीति पर बहस करवाएं । इस विषय की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए कि पुलिस, राजनैतिक दलों एवं गृह मंत्रालय का इस गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने में क्या योगदान रहा है ।

आम जनता से अपील

कृपया आप स्वयं दंतेवाडा जाएं एवं स्थिति का जायजा लें

आप जहां भी हों सलवा जुडुम एवं छत्तीसगढ में हे रहे मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें

छत्तीसगढ में शांति एवं न्याय के लिये मोर्चा (सी पी जे सी):

छत्तीसगढ में शांति एवं न्याय के लिये मोर्चा कुछ उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं का मोर्चा है जो छत्तीसगढ में "आंतरिक आतंकवाद" से लडने के नाम पर हो रहे मानव अधिकारों के हनन से चिंतित हैं । हम सलवा जुडुम द्वारा सरकार की मदद से की जा रही हिंसा से अत्यंत चिंतित हैं जिसने छत्तीसगढ में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी है । हम छत्तीसगढ जन सुरक्षा कानून 2005 से भी चिंतित हैं जिसका उपयोग किसी भी विरोधी स्वर को शांत करने के लिये किया जा रहा है

सम्पर्क : सी पी जे सी, एफ 10/12 मालवीय नगर, नई दिल्ली ई मेल : cpjcindia@gmail.com वेबसाईट : www.cpjc.wordpress.com; Ph: 011-26680883